

*यक वन्यर एफुज-र फि फोय ऐक्ये एल्लः कः क्यः; ओह धि ओफि ह दस ल दल्ल  
एफोफ/क फल्लर &*

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अनुसार लोक अदालत से सिविल मामला निपटने पर दी गई संपूर्ण न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 16 के अनुसार वापस की जायेगी।

*शु जेसकपनः फोः ) ए/ः इन्सक जल्लः , ओ वल्लः W.P. No. 7282/10) ILR(2012)  
MP320 निर्णय द्वारा 01-11-2011 (खण्डपीठ) में प्रतिपादित सिद्धांत –*

- जब कोई मामला सिविल प्रक्रिया 1908 की धारा 89 के अधीन निर्दिष्ट विवाद के निपटारे के ढंगों में से किसी ढंग से निपटा हो।
- तब वादी न्यायालय में दी गई फीस की पूरी रकम वापस प्राप्त कर सकता है।
- इसके लिए उसे न्यायालय से फीस वापसी का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- यह प्रमाण पत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने पर फीस की वापसी कलेक्टर द्वारा की जायेगी।
- न्यायालय फीस की वापसी न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 16 के अनुसार की जायेगी।

*शु नलेकनः , ल - इल्लः फोः ) लः न दक्यक्य , प- (2010) 5 SCC 663 दस ओन ए  
ल ओपः ल्लः कः क्यः; जल्लः फुएु फुल्लः एकि न. ल फु/ल्लः र दः सः; सः फल्लः दः &*

निगोशिएवल इन्सट्रुमेंट एक्ट की धारा 138 के अधीन चेक बाउंस प्रकरण इसी अधिनियम की धारा- 147 के अधीन समझौता योग्य है।

1. मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर, प्रथम या द्वितीय सुनवाई पर – कोई कॉस्ट नहीं
2. मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर – चेक राशि का 10 प्रतिशत
3. जिला एवं उच्च न्यायालय स्तर पर – चेक राशि का 15 प्रतिशत
4. सर्वोच्च न्यायालय स्तर – चेक राशि का 20 प्रतिशत

*ल ओपः ल्लः कः क्यः; जल्लः ओल्लः 2014 ए इरल तल्लः फि फोय विह्य उः  
8614@2014 दस दल्लः ए ; ग फु.ल्लः र दः कः; कः गः ल्लः दः &* यदि चेक बाउंस के प्रकरणों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कराया जाता है, वहां न्यायालय पक्षकारों के मध्य सकारात्मक सोच के कारण हुये समझौते में, यदि उचित समझे तो उपरोक्त कॉस्ट राशि को मामले की परिस्थितियों के अनुसार कम या माफ कर सकती है।

\*\*\*